


09.2025 को प्रार्थीया ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त पत्र को स्वीकार फरमा कर प्रार्थीया की खातेदारी कार्रकारी आराजीयात वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 589/2 रकबा 1.0841 हैक्टर में मुर्तिब प्रार्थीया द्वारा मुर्तिब चाह को नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी में पृथक से दर्ज कर उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित एवं शेष आराजी की किस्म चाही अब्बल दर्ज किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझें वह प्रार्थीया के पक्ष में प्रदान करावें।

हमारे द्वारा प्रार्थीया को सुना गया एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा हस्तगत वाद में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में चाह को नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी में पृथक से दर्ज कर उसकी किस्म गै.मु.चाह अंकित एवं शेष आराजी की किस्म चाही अब्बल दर्ज किये जाने का आदेश करवाने बाबत पेश किया गया है, धारा 131 भू.राज.अधि. के अनुसार "नक्शा ओर क्षेत्र पुस्तक को चालू रखना-सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य समाप्त होने के पश्चात् नक्शा और क्षेत्र पुस्तक राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाये गए नियमों के अनुसार भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा चालू रखी जायेगी तथा वह प्रतिवर्ष या ऐसे लंबे अन्तराल पूरे जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या सम्पदा, खेत की सीमाओं में हुए सब परिवर्तन अभिलिखित कराएगा तथा ऐसी किन्हीं गलतियों का सुधार करेगा जो ऐसे नक्शे या पुस्तक में की गई प्रतीत हों।" एवं धारा 136 के अनुसार "धारा 136 भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह कभी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या किसी भी रजिस्टर में की गई लिपिकीय त्रुटियों या उन त्रुटियों को, जिन्हें संबंधित पक्ष स्वीकार करते हैं, ठीक कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी रजिस्टर में कोई त्रुटि पाता है, तो वह भी उस त्रुटि को सही करने का अधिकार रखता है। हालाँकि, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई त्रुटि पाता है, तो वह बिना पूर्व सूचना दिए उस त्रुटि को नहीं सुधार सकता।" अर्थात् धारा 131, 136 भू.राज.अधि. केवल राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं प्रार्थी की बहस के अनुसार वादअधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रार्थीया द्वारा वांछित अनुतोष उक्त धारा 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत देय नहीं है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को न्यायालय में विचाराधीन रखने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज.अधि. के प्रावधानों के अनुसार पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

न्यायहित में तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि में यदि चाह खुदा हुआ है तो राज. कार्रकारी अधिनियम एवं भू. राज.अधि. एवं राजस्व नियमों के अनुसार मौके पर नापचौक कर किये का अंकन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)